



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 127 राँची, गुरुवार 3 पौष, 1937 (श०)
24 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

9 अक्टूबर, 2015

1. निगरानी आयुक्त, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-200, दिनांक 9 फरवरी, 2010.
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का आदेश सं०-6197, दिनांक 13 अक्टूबर, 2010; संकल्प सं०-6198, दिनांक-13 अक्टूबर, 2010; पत्रांक-6761, दिनांक 14 नवम्बर, 2011 तथा संकल्प सं०-949, दिनांक 2 फरवरी, 2012.
3. श्रीमती मृदुला सिन्हा, तत्कालीन प्रधान सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1782, दिनांक 22 सितम्बर, 2011.

संख्या- 5/आरोप- 1-362/2014 का.-8909--श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-495/03, गृह जिला-नवादा, बिहार), के भूमि सुधार उप समाहर्ता, राँची की कार्यावधि से संबंधित आरोप निगरानी आयुक्त, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-200, दिनांक 9 फरवरी, 2010 द्वारा प्रतिवेदित किये गये हैं। श्री प्रभात पर आरोप है कि इनके द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 एवं 48 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 11 राजस्व वादों में अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति दी गयी है एवं निगरानी थाना कांड सं0-26/2008 के नामजद अभियुक्त श्रीमती मेनन एक्का को गैर वैधानिक लाभ पहुँचाया गया है। इस प्रकार, श्री प्रभात द्वारा जनजातीय हितों के प्रति उदासीनता, कर्तव्यहीनता तथा अनुशासनहीनता बरती गयी है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उक्त आरोपों हेतु श्री प्रभात को विभागीय आदेश सं0-6197, दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 द्वारा निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-6198, दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती मृदुला सिन्हा, तत्कालीन सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री प्रभात द्वारा समर्पित बचाव-बयान निम्नवत् है:-

(क) प्रश्नगत वादों में अधिनियम की धारा-46 एवं 48 अंतर्गत आवेदन दिया गया है। आवेदन देने के पश्चात् ओरमाँझी अंचल के अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। संबंधित सूचना निर्गत किया गया तथा आवेदक का बयान लेते हुए शपथ-पत्र भी प्राप्त किया गया। अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सभी संबंधित कागजातों को उनके पेशकार द्वारा अभिलेख बंद करते हुए अंतिम आदेश के लिए उपस्थापित किया गया। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में जाँच करने हेतु अलग से कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।

(ख) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम अंतर्गत Resident तथा Local limits of area of the Police Station को पारिभाषित नहीं किया गया है। इस अधिनियम की धारा-46 को वर्ष 1947 में संशोधित किया गया एवं उस समय भी इन शब्दों को पारिभाषित नहीं किया गया । जब यह अधिनियम प्रभावी हुआ तब पुलिस थाना का क्षेत्र काफी बड़ा होत था । जनसंख्या में बढ़ोतरी तथा प्रशासनिक कारणों से नए थानों का सृजन हाता गया तथा उसका आकार भी छोटा होता गया। जिस प्रकार पुलिस थाने की अवधारणा बदलती गयी, उसी प्रकार Resident के अर्थ भी बदलते रहे। स्थायी निवासी का अर्थ संबंधित व्यक्ति के पूर्वजों के निवास से संबंधित रहा है परंतु इस अधिनियम की धारा-46 अंतर्गत इसे Local limits of area of the Police Station से संबद्ध कर देखा जाने लगा। जब छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब अविभाजित राँची जिले में मात्र 18 थाने थे, जिसमें सदर अनुमंडल, राँची अंतर्गत 5 थाने थे जबकि वर्तमान में मात्र राँची शहर में 10 से अधिक थाने हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में कहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन थानों के आधार पर अधिनियम की धारा-46 अंतर्गत निर्णय लिया जाय।

(ग) W.P.(C) No.- दशरथ उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य; L.P.A. No.- 666/05- दशरथ उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा S.L.P. No. -5354/07- दशरथ उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश से स्पष्ट है कि अलग-अलग थाना के अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बीच भूमि हस्तांतरण को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अवैध नहीं माना है।

(घ) इनके द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने न्यायालय के माध्यम से अधिनियम की धारा-46/48 अंतर्गत भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी गयी है। इस निर्णय के विरुद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-215 अंतर्गत अपील की जा सकती है। भूमि के निबंधन पट्टा का रद्द करने हेतु सक्षम सिविल कोर्ट में अपील की जा सकती है जो प्रश्नगत मामले में नहीं

किया गया। इनके द्वारा पारित आदेश को न तो कहीं चुनौती दी गयी है और न ही किसी सक्षम अपीलीय प्राधिकार द्वारा उनके आदेश को रद्द किया गया है।

(ड) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्द्ध न्यायिक प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को misconduct की श्रेणी में नहीं माना है।

श्रीमती मृदुला सिन्हा, तत्कालीन प्रधान सचिव; समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड -सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1782, दिनांक 22 सितम्बर, 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसका निष्कर्ष निम्नवत् है:-

(क) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में स्थानीय निवासी की परिभाषा दी गयी है, जो एक्ट के अनुसार उसी पुलिस थाना अंतर्गत निवास करते हैं। प्रश्नगत मामले में क्रेता के पति श्री एनोस एक्का इस वाद में आदेश पारित होने के समय मंत्री थे तथा यह सर्वविदित था कि सिमडेगा जिला के निवासी थे एवं उस समय डोरंडा में रह रहे थे।

(ख) आरोपी का यह कहना कि निवासी शब्द एक्ट में पारिभाषित नहीं है, आधारहीन है। एक्ट इस संबंध में स्पष्ट है तथा आरोपी पदाधिकारी जानबूझ कर दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

(ग) आरोपी का यह कहना कि थाना-क्षेत्र समय-समय पर बदलता रहा है, विषय से परे है क्योंकि आदेश पारित करते समय आवेदक का पारिभाषित पुलिस थाना निवासी होना आवश्यक है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का खुल्लमखुला उल्लंघन किया गया है।

(घ) आरोपी पदाधिकारी का यह तर्क सर्वथा अनुचित है कि अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के तहत पारित आदेश की जाँच नहीं की जा सकती। Malafide intention से पारित आदेश की समीक्षा की जा सकती है।

श्री प्रभात के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री प्रभात के विरुद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु वृहत् दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिए विभागीय पत्रांक- 6761, दिनांक 14 नवम्बर, 2011 द्वारा श्री प्रभात से द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी। श्री प्रभात के पत्र, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपना उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें निम्नवत् तथ्य दिये गये हैं:-

(क) संचालन पदाधिकारी ने उनके बचाव-बयान पर ध्यान दिये बिना ही आरोपों को प्रमाणित बताया है। इन्होंने कभी नहीं कहा है कि "क्रेता ओरमाँड़ी थाना के निवासी नहीं थे।" संचालन पदाधिकारी द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना तथ्यपरक नहीं है।

(ख) आरोप से संबंधित 11 वादों में वाद सं0-74/06-07-ननकू मुण्डा वगैरह बनाम राज्य के मामले में श्री रजत कुमार गुप्ता के आपत्ति आवेदन के आलोक में खरीद-बिक्री के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। शेष 10 वादों में उनका आदेश आज भी यथावत् है। आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आदेश विधिसम्मत है।

(ग) एक ही थाना के निवासी के संबंध में जाँच करना राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी/अंचल निरीक्षक का दायित्व है। क्रेता-विक्रेता एक ही थाने के नहीं हैं, इस तरह की शिकायत उनके न्यायालय को प्राप्त नहीं थी।

(घ) प्रक्रिया के तहत अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेने की व्यवस्था है। व्यक्तिगत जानकारी या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया में वादों का निष्पादन नहीं किया जाता है। अगर यह मान भी लिया जाय कि उन्हें एनोस एक्का के मंत्री होने या उनके सिमडेगा जिले के निवासी होने की जानकारी थी तो भी अभिलेख में इस प्रकार का कोई तथ्य जाँच-प्रतिवेदन के आधार पर उनके संज्ञान में नहीं लाया गया।

(ड) पूर्व में समर्पित बचाव-बयान को पुनः उद्धृत करते हुए करते हुए श्री प्रभात द्वारा कहा गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम अंतर्गत निवासी एवं स्थानीय शब्द को पारिभाषित नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी ने इस तथ्य को आधारहीन बताया है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत इसे पारिभाषित किया गया है।

(च) श्री दशरथ उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग पुलिस थानों के निवासियों के बीच अनुसूचित जनजाति की भूमि की खरीद-बिक्री को अवैध नहीं माना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के इस आदेश के विरुद्ध की गयी अपील को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री उराँव ने L.P.A. दायर किया, जो खारिज हो गया। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A. में पारित आदेश के विरुद्ध श्री उराँव ने S.L.P. दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। सभी न्यायालयों ने निचली न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

श्री प्रभात द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रभात द्वारा कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, बल्कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में दिये गये बचाव-बयान को ही समर्पित किया है। तदुसार, विभागीय संकल्प सं0-949, दिनांक 2 फरवरी, 2012 द्वारा श्री प्रभात को निलंबन मुक्त करते हुए इनके विरुद्ध निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किया गया-

1. इनकी तीन वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक ।
2. प्रोन्नति की देय तिथि से अगले तीन वर्षों तक प्रोन्नति बाधित ।
3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी देय नहीं होगा।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री कार्तिक कुमार प्रभात, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्रांक-2262, दिनांक 5 जुलाई, 2012 द्वारा महामहिम राज्यपाल को

अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2262, दिनांक 5 जुलाई, 2012 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। इसमें श्री प्रभात द्वारा निम्नवत् तथ्य अंकित किये गये हैं-

(क) श्री प्रभात का कहना है कि इनके मामले में एकपक्षीय कार्रवाई की गयी है तथा इन्हें समुचित अवसर से वंचित किया गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन में प्रस्तोता पदाधिकारी किसी तिथि को उपस्थित नहीं हुए और न ही इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य/कागजात प्रस्तुत किया गया। संचालन पदाधिकारी ने तिथिवार अभिलेख का संधारण नहीं किया है।

(ख) श्रीमती मेनन एक्का ने थाना-डोरंडा, ओरमांडी आदि स्थानों पर वहाँ का स्थानीय पता देकर भूमि क्रय किया है। स्थानीय पता का उल्लेख निवास को आच्छादित करता है और उसे अस्वीकार करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-215 अंतर्गत अपील का प्रावधान है, जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विक्रय की स्वीकृति को अवैध घोषित नहीं किया जाय, तब तक इसे अनियमित नहीं ठहराया जा सकता।

श्री प्रभात के अपील अभ्यावेदन की विधिकक्षा (vetting) हेतु संचिका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को पृष्ठांकित की गयी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा विषयगत मामले में परामर्श हेतु संचिका विधि(न्याय) विभाग, झारखण्ड को भेजी गयी। विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिया गया परामर्श निम्नवत् है:-

“In the case of Shasthi Pado Shekhar Vs. Anandi choudhary reported in AIR 1967 Patna at page-25, wherein it has been reiterated that the word Resident as used in section-46 of the CNT Act meant one having a permanent place of Abode and did not include temporary or occasional residence.”

विधि(न्याय) विभाग, झारखण्ड से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में विषयगत मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी ने श्रीमती

मेनन एक्का के पक्ष में आदिवासी भूमि के विक्रय के लिए अपने अपील अभ्यावेदन में 'Resident' को गलत ढंग से उद्धृत किया है और इनके द्वारा क्रेता के पक्ष में आदिवासी भूमि के लिए दी गयी अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 एवं 48 के प्रावधान के प्रतिकूल है । समीक्षोपरांत, श्री प्रभात का अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।
